



**Satyjit Roy Will Get A Statue In Rajasthan**

Tour guides take visitors through the locations where Sonar Kella was shot, there are signs that point towards "Mukul Bari".

**The English Calendar Riots of 1752**

How our calendars lost 11 days in September 1752

# राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro



भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने शनिवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर भाजपा के चुनावी कार्यक्रमों का जोर-शोर से शंखनाद कर दिया है। नड्डा ने रणथम्भौर के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की तथा उसके बाद परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना किया। गणेश मंदिर में नड्डा के साथ मिलकर प्रदेश भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उसके बाद दशहरा मैदान में नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया, इस मौके पर मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ व पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया भी मौजूद रहे। सबसे पहले मंच से भाजपा के परिवर्तन यात्रा के स्टीकर का विमोचन किया गया, उसके बाद जनसभा हुई व अंत में जे.पी. नड्डा ने परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना किया। जनसभा के दौरान वसुंधरा राजे ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मामले में मु.मंत्री गहलोत पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि, इसका दुष्परिणाम प्रदेश की भौली-भांति जनता को भुगतना पड़ रहा है।

## घर को लूटने वाली गहलोत सरकार को बदलना जरूरी: जे.पी. नड्डा

**भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने रणथम्भौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई**

जयपुर/सवाईमाधोपुर 2 सितम्बर (का.सं.) सवाईमाधोपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान हुई जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर गहलोत सरकार को गहलूट सरकार यानी घर को लूटने वाली सरकार बताया। लेकिन, उनका अधिक फोकस राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी दलों के गठबंधन की आलोचना पर रहा। उन्होंने कहा कि, ये सभी सिर्फ अपने परिवारों को बचाने के लिए मिले हैं। ये मिल कर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, जबकि मोदी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि, आम

- इस अवसर पर आयोजित जनसभा को जे.पी. नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी तथा नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ व अन्य नेताओं ने संबोधित किया।
- वसुंधरा राजे ने ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट का मसला उठाया और गहलोत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ज्ञातव्य है कि, यह मुद्दा भाजपा के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।
- प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी ने हिन्दुत्व पर फोकस रखा व जय श्रीराम के नारे लगाए, वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने गिरती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया व कहा कि, चार साल में तीन हजार बार पुलिस पिटी फिर कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी।

साथ हुआ। इसके बाद दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के "स्टिकर" का विमोचन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजस्थान के इस हिस्से में भाजपा के लिए इस बार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ई.आर.सी.पी. एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और परिवर्तन यात्रा की पहली सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुद्दे पर ना सिर्फ लम्बी बात की, बल्कि गहलोत सरकार पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि, राजे के अलावा अन्य किसी भी नेता ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान में इस परियोजना को बड़ा मुद्दा बना रखा है और पिछले दिनों केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खुद जलशक्ति मंत्री (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

**क्या आपको कम सुनाई देता है?**  
ऑटोमेटिक कान की मशीनों स्पीच थेरेपी कॉकिलियर इम्प्लांट, ऑटिज्म डिब्ले स्पीच, हकलाना, तुतलाना  
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS  
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR  
सम्पर्क- 94602 07080

**'राफेल्स होटल रिसॉर्ट में 1.27 करोड़ रु. नकद मिले'**  
उदयपुर, 2 सितम्बर (का.सं.)। नई दिल्ली से आयी एनफॉसमेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) की टीमों ने गत 28 अगस्त को वर्षा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के राफेल्स होटल रिसॉर्ट, ट्राइटन होटल रिसॉर्ट पर की गई

■ ई.डी. ने राफेल्स होटल रिसॉर्ट पर 28 अगस्त को की गई रेंड के बारे में खुलासा करते हुए बताया। रेंड के बारे में कई खुलासे किए हैं। ई.डी. द्वारा दी गयी अधिकृत जानकारी के अनुसार इस ग्रुप और इसके डायरेक्टर्स पर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है। कार्रवाई में ई.डी. ने खुलासा किया है कि ग्रुप और इसके डायरेक्टर्स द्वारा होटल के डवलपमेंट के लिए बड़े स्तर पर विदेशी निवेश लिया गया है, यह निवेश ग्रुप ने मॉरिशस की शिवाजर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए लिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जनता जब त्राहिमा हो जाए तो भाजपा के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हो जाती है कि, परिवर्तन के लिए काम करे इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। नड्डा ने कहा, यहां की सरकार यहां के लोगों को लूट कर दिल्ली के लोगों का घर भरती है। इनकी इच्छा है भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को पनाह दो और यह पैसा दिल्ली में बैठे लोगों को भेजो। गहलोत सरकार का मतलब है लाल डायरी। सरकार के मंत्री ने लाल डायरी की बात की तो उसे बर्खास्त कर दिया अब हमें ऐसी सरकार को ही बर्खास्त करना है। उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि, जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र घर -घर नल लगावा रहे हैं और गहलोत जी जलजीवन मिशन में घोटाळा कर रहे हैं। ई.डी.ने योजना से जुड़े अधिकारियों व ठेकेदारों से भारी नकदी जब्त की है। राजस्थान की छवि बदलनी है तो सरकार बदलनी है। शनिवार को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज रणथम्भौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के

कर सकती है। अब तक ई.डी. ने जिन ठेकेदार, प्रॉपर्टी कारोबारी, लाइज़नर और जलदाय विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि, उससे बड़े फर्जीवाड़े में बड़े अधिकारियों की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हुआ होगा। जानकारी के अनुसार, प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह कव्या के साथ अधिकारियों के संबंधों को लेकर ई.डी. को कई इनपुट मिले हैं। साथ ही कुछ जमीनों और फार्म हाउस की जानकारी मिली है। कल्याण सिंह ने इसकी जानकारी ई.डी. को दी है, क्योंकि जांच में सामने आया है कि, प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह मंत्री, विधायक, आई.ए.एस. व आई.पी.एस. अधिकारियों का पैसा जमीनों में लगाता

है। कहा जा रहा है कि, वैशाली नगर, करणी पैलेस रोड, गांधी पथ सहित कई इलाकों में प्रॉपर्टी का व्यापार करने वाले कल्याण सिंह कव्या के घर से ई.डी. को

## ई.डी. के रडार पर महेश जोशी के करीबी कई ब्यूरोक्रेट्स व राजनेता

दो दिन की कार्यवाही में ई.डी. ने कई अहम दस्तावेज जुटाए

- अधिकारियों को सर्च के दौरान ढाई करोड़ रुपए कैश और सोने की ईंट के साथ प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया और कल्याण सिंह कव्या के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।
- इसके बाद कहा जा रहा है कि, सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी सुबोध अग्रवाल से भी पूछताछ की जा सकती है।
- जिन ठेकेदार, प्रॉपर्टी कारोबारी, लाइज़नर और जलदाय विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की गई है, उससे ई.डी. ने अंदाजा लगाया है कि, इस बड़े फर्जीवाड़े में बड़े अधिकारियों की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हुआ होगा।

कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के हैं। इस आधार पर पुलिस व ई.डी. इन अधिकारियों और नेताओं से जमीनों में लगाए पैसों को लेकर पूछताछ करेगी। ज्ञातव्य है कि, संजय बड़ाया को चार दिन पहले ही विदेश दौरे से जयपुर लौटने पर जानकारी मिली थी कि ई.डी. राजस्थान में कभी भी जल जीवन मिशन को लेकर एक्शन कर सकती है। इस पर संजय ने दो दिन पहले ही अपना आईफोन बदलकर उसकी जगह दूसरा मोबाइल 31 तारीख को ही लिया था। ईडी को बड़ाया के घर से नकदी तो नहीं मिली, लेकिन जो दस्तावेज मिले वो ई.डी. की जांच आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दस्तावेजों में, कई अधिकारी, राजनेताओं को पैसा देने

और लेने के सबूत बताए जा रहे हैं। कुछ रजिस्ट्री के दस्तावेज भी बड़ाया के घर से ई.डी. को मिले हैं। बताया जा रहा है कि, रिटायर आई.ए.एस. अधिकारी अमिताभ कौशिक के घर ई.डी. को डेढ़ करोड़ रुपए नकद, एक किलो गोल्ड और निवेश के कई दस्तावेज मिले। अमिताभ कौशिक के साथ ई.डी. वन टू वन कर रही है। कौशिक की संपत्ति का ब्योरा भी निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर ई.डी. कौशिक से मुख्यालय बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है। कहा जा रहा है कि, उन्हें जल्द नोटिस दिया जा सकता है। कौशिक को रिमांड पर भी ले सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने गहलोत की अदालतों में भ्रष्टाचार संबंधी बयानबाजी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गहलोत को आदेश दिया कि, वे 3 अक्टूबर तक जवाब दें कि, उन्होंने किस आधार पर बयानबाजी की। गहलोत से पूछा है कि उन्होंने क्यों और किस आधार पर यह बयान दिया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जातिगत सर्वे के जवाब में केन्द्रीय सरकार हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जी. रोहिणी की रिपोर्ट पेश करेगी

रोहिणी आयोग ने अपनी 1100 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि, ओ.बी.सी. के एक वर्ग (यादव) ने ओ.बी.सी. वर्ग के लिये आरक्षित अधिकांश सरकारी सुविधाओं व रियायतों के लाभ पर कब्जा कर लिया है

-श्रीनंद झा-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। बिहार सरकार का "कास्ट सर्वे" तो कानूनी व प्रक्रियात्मक लड़ाई में फंसा हुआ है, वहीं, नरेन्द्र मोदी सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को पेश करके ओ.बी.सी. का समर्थन हासिल करने की अपनी योजना को सामने लाएगी। बिहार सरकार द्वारा कराये जा रहे जाति सर्वेक्षण (कास्ट सर्वे) से संबंधित एक याचिका के सिलसिले में केन्द्र सरकार ने दलील दी है कि इस प्रकार का सर्वे कराने के लिए केवल केन्द्र सरकार ही अधिकृत है। लेकिन 18 अगस्त के अपने आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के जातिगत सर्वे के आँकड़ों के प्रकाशन पर "स्टे" देने से इनकार कर दिया था। जहाँ बिहार-सर्वे के आँकड़े अभी विचारार्थीन स्थिति में हैं, वहीं संसद में

- बिहार के कास्ट सर्वे से संबंधित एक याचिका की सुनवाई में केन्द्र सरकार ने कहा था कि, सिर्फ केन्द्र सरकार ही ऐसा सर्वे करवा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कास्ट सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
- जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन सभी ओ.बी.सी. वर्गों को चिन्हित करने तथा उन्हें उप वर्गों में वर्गीकृत करने के लिये हुआ था। रोहिणी कमीशन ने ओ.बी.सी. की विभिन्न जातियों व समुदायों की भारी असमानता को देखा और सरकारी योजनाओं के न्यायोचित वितरण के मानदंड व तौर-तरीके सुझाए।
- जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन 2017 में किया गया था और जुलाई में इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पेश की गई थी।

पहचान करने तथा उन्हें उप-श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने के आदेश दिये गये थे। यह आयोग ओ.बी.सी. के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न जातियों एवं समुदायों की विषमताओं एवं असंगतियों की गहराई में गया था तथा सरकारी योजनाओं के लाभों के उचित एवं निष्पक्ष वितरण के तरीकों, आधारों तथा शर्तों के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ऐसी संभावना है कि जुलाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई यह रिपोर्ट 18 सितम्बर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में प्रस्तुत कर दी जायेगी। पिछले चुनावों में, भाजपा को ऊँची जातियों के समर्थन के अलावा, ओ.बी.सी. के समर्थन का भी लाभ मिला है। भाजपा का कहना है कि ओ.बी.सी. के लिये लाई गई सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ओ.बी.सी. के केवल एक वर्ग- (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पेश करने केन्द्र सरकार मौके का फायदा उठाकर सारा श्रेय स्वयं लेने की ताक में है। केन्द्र सरकार ने 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया तथा आयोग को सभी ओ.बी.सी. जातियों की

नड्डा की वरिष्ठों को हिदायत

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिये किन्हीं खास प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश नहीं करें। वे सीटों के लिये उचित प्रत्याशी को लेकर अपने विचार निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं।

■ भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ नेताओं को हिदायत दी है कि, वे किसी प्रत्याशी की सिफारिश न करें।

## आज़ाद व अधीर रंजन "एक राष्ट्र एक चुनाव" कमेटी में शामिल

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सात अन्य सदस्य हैं

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। विधि मंत्रालय ने शनिवार को "एक राष्ट्र, एक चुनाव" कमेटी को लेकर एक अधिसूचना जारी की। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा, इसके सात अन्य सदस्य इस प्रकार हैं-गृहमंत्री अमित शाह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, सुभाष सी. कश्यप, हरीश साल्वे तथा संजय कोठारी।

- कमेटी के सात सदस्य हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, लोकसभा के सैंक्रेटरी जनरल सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे एवं पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी।
- कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित के रूप में बैठकों में शामिल होंगे तथा विधि मामलात सचिव नितेन चन्द्रा पैनल के सचिव होंगे।
- कमेटी, संविधान, जन प्रतिनिधित्व कानून व अन्य नियम कायदों में ऐसे संशोधनों का सुझाव देगी, जो एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक होंगे।

विधिक मामलों के सचिव नितेन चन्द्र इस पैनल के सचिव होंगे। बताया जा रहा है कि, रिटायर आई.ए.एस. अधिकारी अमिताभ कौशिक के घर ई.डी. को डेढ़ करोड़ रुपए नकद, एक किलो गोल्ड और निवेश के कई दस्तावेज मिले। अमिताभ कौशिक के साथ ई.डी. वन टू वन कर रही है। कौशिक की संपत्ति का ब्योरा भी निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर ई.डी. कौशिक से मुख्यालय बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है। कहा जा रहा है कि, उन्हें जल्द नोटिस दिया जा सकता है। कौशिक को रिमांड पर भी ले सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संशोधनों की सिफारिश करेगी। यह कमेटी इस बात का भी निरीक्षण-परीक्षण करेगी कि, क्या संबंधित संविधान संशोधनों की अभिपुष्टि (रिटिफिकेशन) राज्यों में कराया जाना जरूरी है। कमेटी एक साथ चुनाव होने की स्थिति में विभिन्न (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट का सी.एम. गहलोत को नोटिस

जयपुर, 2 सितंबर (का.सं.)। राजस्थान हाइकोर्ट ने न्यायपालिका पर बयानबाजी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तीन अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। अदालत ने सीएम